



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 2012/चैत्र 20, 1934

No. 90]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 2012/CHAITRA 20, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2012

विषय : चीन जन. गण. मूल के या वहां से निर्यातित "इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 14/6/2011-डीजीएडी.—मै0 डब्ल्यूएस इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड मै0 मार्न इन्सुलेटर्स लिमि; मै0 इन्सुलेटर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी एवं मै0 आदिम्य बिरला नुवो लिमि0 ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वरतुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात संबंध देश कहा गया है) मूल के या निर्यातित इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वरतु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच शुरू करने के लिए इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमि., मै0 मार्डन इन्सुलेटर्स लिमि0, मै0 इन्सुलेटर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी एवं मै0 आदित्य बिरला नुवो लिमि0 ने संगत जानकारी प्रदान कर दी है।

2. और यतः, प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश के मूल के या निर्यातित संबद्ध वरतु के पाटन और घरेलू उद्योग को "क्षति" के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोजित ठहराने के लिए कथित पाटन एवं "क्षति" के बीच आकस्मिक संबंध है।

इसलिए प्राधिकारी कथित पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में एतद्वारा पाटनरोधी नियमों के नियम 5 में दी गई शर्तों के अनुसूप, कथित पाटन की अवस्थिति, उसकी डिग्री और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क, यदि आरोपित किया जाता है, की ऐसी राशि की संस्तुति को करने के लिए जो घरेलू उद्योग को "क्षति" से बचाने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी जांच प्रारम्भ करता है।

### घरेलू उद्योग और स्थिति

3. यह याचिका डब्ल्यूएस इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमि. मार्डन इन्सुलेटर्स लिमि, इन्सुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्पनी एवं आदित्य बिरला नुवो लिमि० द्वारा दायर की गई है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के कई अन्य उत्पादक भी हैं। प्राधिकारी ने नोट किया है कि मार्डन इन्सुलेटर्स लिमिटेड, इन्सुलेटर्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स कम्पनी और आदित्य बिरला नुवो लिमि० ने प्रमाणित किया है कि विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि डब्ल्यू एस इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमि० ने जॉच की अवधि के दौरान काफी आयात किया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि डब्ल्यूएस इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमि० कम्पनी द्वारा किए एग आयातों के आलोक में अपात्र घरेलू उद्योग है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बाकी तीन याचिकाकर्ताओं अर्थात् मार्डन इन्सुलेटर्स लिमि०, इन्सुलेटर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी एण्ड आदित्य बिरला नुवो लिमि० की जॉच की अवधि के दौरान कुल उत्पादन, भारतीय उत्पादन से डब्ल्यूएस इण्डस्ट्रीज का उत्पादन अलग करके 67% बनता है। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि वर्तमान याचिका दायर करने और पाटनराधी नियम के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में इन तीन याचिकार्ताओं का आधार बनता है।

### विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जॉच के उद्देश्य के लिए विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. मूल का या उससे निर्यातित "पोर्सिलीन, सिरैमिक या सीसो का बना हुआ, या असेम्बल्ड या अनअसेम्बल्ड, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स" है।

याचिकाकर्ताओं ने आत्मनिवेदन किया है कि इन्सुलेटर पोर्सिलीन या ग्लास का हो सकता है। पोर्सिलीन इन्सुलेटर्स का उत्पादन मृत्तिका, सिलिका, फिल्डरपार और धातु पाटर्स से होता है। जबकि ग्लास इन्सुलेटर्स का उत्पादन सिलिका और मेटल पाटर्स का उपयोग करके होता है। इन दोनों प्रकार की मदों के गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्यों, प्रयोगों और कीमतों पर विचार करते हुए ये दोनों एक ही मद बनते हैं। वस्तुतः यह उत्पाद तकनीकी रूप से न्यूट्रल उत्पाद है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ने इन्सुलेटर्स जो ग्लास या पोर्सिलीन का हो सकता है, का अधिप्रापण करने के लिए निविदा निकाली है। निगम ने ग्लास और पोर्सिलीन इन्सुलेटर्स के बीच कोई विभेद नहीं किया है और उनका केवल कीमतों के आधार पर आर्डर दिया है। निगम ने दोनों उत्पादों के बीच कोई तकनीकी भेद नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कभी-कभी "ग्लास" या "पोर्सिलीन" का संदर्भ दिए बिना बीजक तैयार किया जाता है। ग्लास इन्सुलेटर्स के बारे में उपलब्ध वाणिज्यिक एच्वास में "ग्लास" का उल्लेख नहीं किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत आयात आंकड़ों में कई जगह पर "ग्लास" का उल्लेख नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दोनों उत्पादों में केवल कच्चे माल और उत्पादन तकनीक का अंतर है जिससे मद का कोई विभेदकारी अन्तर नहीं बनता है। दो अलग-अलग तकनीकों द्वारा उत्पादित मद स्पष्टतः एक मद बनती है। इस कारण यह उत्पादन तकनीकी रूप से न्यूट्रल उत्पाद है।

इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर का मुख्य कार्य उच्च बोल्टेज ऐरिया में एक सुचालक वरतु को दूसरी सुचालक वस्तु से इन्सुलेट करना या किसी ऐसी वस्तु को इन्सुलेट करना है जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को आस-पास के ऐसे क्षेत्र में परेषित कर सके जहाँ इलेक्ट्रिक ऊर्जा का परेषण करने से बचा जाता है।

इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स का टिपिकल उपयोग बुशिंग, डिस्कनेक्टर्स, सर्किट, ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसमिशन और रेलवे, इलेक्ट्रोरेटिक पर्सिपिटेटर्स आदि सहित वितरण लाइनों में होता है। ग्लास या पोर्सिलेन इन्सुलेटर्स को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 105 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्षक 8546 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

### समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिसका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के सदृश है। पाटित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, प्रकार्यों अथवा अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उन्हें पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत समान वस्तु माना जाए।

अतः मौजूदा जाँच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में मानता है।

### शामिल देश

6. मौजूदा जाँच में अंतर्गत देश चीन जन.गण. है।

7. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने भारत में उत्पादन कीमत के आधार पर विधिवत समायोजन करके यह उल्लेखनीय करते हुए सामान्य कीमत का दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में लागत या कीमत पर विचार करने के लिए तृतीय देश उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा दावाकृत सामान्य मूल्य पर जाँच प्रारम्भ के उद्देश्य से विचार किया गया है।

### निर्यात कीमत

8. याचिकाकर्ताओं ने भारत में आयातों का मूल्य एवं उनकी मात्रा का आकलन करने के लिए चीन के सीमाशुल्क आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। निवल निर्यात कीमत का अकलन करने के लिए कीमत समायोजन कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा और बैंक प्रभार के आधार पर किया गया है।

### पाटन मार्जिन

9. याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य का पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश में उत्पादित या वहाँ से निर्यात संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी जाँच शुरूआत करना न्यायोचित है।

### **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

10. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आंकलन करने के लिए डब्ल्यूएस उद्योग को प्रथम कारके तीनों याचिकाकर्ताओं की सूचना पर विचार किया गया। याचिकाकर्ताओं ने समग्र रूप में आयातों की संबद्धित पाटित मात्रा के कारण कथित रूप से हो रही "क्षति" के संबंध में तथा भारत में उत्पादन एवं खपत, कीमत में अत्यधिक गिरावट होने और कीमतों में हास होने तथा उनका उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, इंवेन्ट्रिज, बाजार हिस्सा, लाभ, लगाई गई पूँजी पर आय तथा घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को की जा रही क्षति के पर्याप्त साक्ष्य है जिससे पाटनरोधी जाँच शुरू करना न्यायोचित होता है।

### **11. जाँच अवधि (पीओआई)**

वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 (12 माह) है। तथापि क्षति जाँच अवधि में अप्रैल, 2008- मार्च, 09, अप्रैल, 2009- मार्च, 2010, अप्रैल, 2010- मार्च, 2010 और जाँच अवधि शामिल होंगे। सामग्री क्षति की चुनौती के कारण जाँच अवधि के पश्चात के आंकड़ों की जाँच भी की जाएगी।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

12. संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारें, भारत के ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से निम्नलिखित पते पर लिखित में जाँच से संगत निवेदन कर सकता है:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**कमरा सं. 243,**  
**उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011**

### **समय सीमा**

13. इस जाँच से संबंधित कोई भी जानकारी लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए जिससे की यह इस अधिसूचना की तारीख से प्राधिकारी के उपर्युक्त पते पर 40 दिनों के भीतर पहुंच जाए। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

### अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. सभी हितबद्ध पक्षकार उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में एक अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे। गोपनीय सूचना का अगोपनीय अंश अथवा अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत हो जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की एक अर्थपूर्ण समझ प्राप्त हो सके। यदि सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

15. उपर्युक्त पैराग्राफ में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा सामान्य या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

16. नियम 6(7) के अनुसारण में प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

### असहयोग

17. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

1283 5/12-2

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIAL NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2012

**Subject :** Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of 'Electrical Insulators' originating in or exported from China PR.

No. 14/8/2011-DGAD— M/s WS Industries (India) Ltd., M/s Modern Insulators Limited; M/s Insulators and Electrical Company and M/s Aditya Birla Nuvo Ltd have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of electrical Insulators (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country). M/s WS Industries (India) Ltd., M/s Modern Insulators Limited; M/s Insulators and Electrical Company and M/s Aditya Birla Nuvo Ltd have provided the relevant information.

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country; 'injury' to the domestic industry; and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**Domestic Industry & Standing**

3. The petition has been filed by WS Industries (India) Ltd., Modern Insulators Limited; Insulators and Electrical Company and Aditya Birla Nuvo Ltd. There are a number of other producers of the product under consideration in India. The Authority has noted that Modern Insulators Limited, Insulators and Electrical Company and Aditya Birla Nuvo Ltd have certified that there are no imports of the product under consideration. The Authority has also noted that WS Industries (India) Ltd has made significant imports during the period of investigation (POI). The Authority has, therefore, considered WS Industries (India) Ltd as ineligible domestic industry in view of significant imports made

by the company. The Authority further notes that the total production of the remaining three petitioners, viz., Modern Insulators Limited; Insulators and Electrical Company and Aditya Birla Nuvo Ltd during the Period of Investigation (POI) is 67 % after excluding production of WS Industries from Indian production. The Authority, therefore, concludes that these three petitioners have standing to file the present petition and constitute the Domestic Industry within the meaning of the Anti Dumping Rules.

### **Product under consideration**

4. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Electrical Insulators made of porcelain/ ceramic or glass, whether assembled or unassembled" originating in or exported from China PR.

The petitioners have submitted that Insulators can be either of porcelain or of glass. Porcelain Insulators are produced using clay, silica, feldspar and metal parts; while glass insulators are produced using silica and metal parts. Both constitute one article, considering the characteristics of these two types, manufacturing process, functions, uses and prices. In fact, the product is a technology neutral product. Power Grid Corporation has floated tenders for procurement of insulators which can be of glass or porcelain. The Corporation has placed no distinction between glass and porcelain insulators and has placed orders solely on the basis of prices. The Corporation has not made any technical distinction between the two products. Further, it is noted that the product is sometimes invoiced by the suppliers without reference to "glass" or "porcelain". The commercial invoice available in respect of manufacturers of glass insulators does not refer to "glass". Import data of the product under consideration also at several instances does not refer to "glass". It is, thus, evident that the mere difference in the two types is in the form of raw material and production technology, which does not lead to two distinct articles. The article produced through two different technologies clearly constitutes one article only. That is why the product is a technology neutral product.

The main function of Electrical Insulator is to insulate one conducting body from another at high voltage areas, or to insulate a body which can transmit electrical energy to the surrounding, at areas where such transmission of electrical energy has to be avoided. Typical applications of electrical insulators are in Bushings, Disconnectors, Circuit breakers, Transformers, Power transmission and distribution lines, including railways, Electrostatic Precipitators etc. Glass or Porcelain insulators are classified under customs heading 8546 under Chapter 85 of the Customs Tariff Act.

### **Like Articles**

5. The Petitioners have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imported goods and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules.

12839 112-3

Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

### **Subject Country**

6. The country involved in the present investigation is China PR.

### **Normal value**

7. The Petitioners have submitted that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with para-7 of Annexure-I to the Rules. The petitioners have claimed normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted; stating that consideration of cost or price in a market economy third country is not available. The Normal value claims by the Petitioners have been considered for the purposes of initiation.

### **Export Price**

8. The Petitioners have claimed export prices on the basis of China Customs data to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been made on account of commission, port expenses, inland freight and bank charges to arrive at the net export price.

### **Dumping Margin**

9. The Petitioners have provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject country are significantly higher than the net export prices, *prima-facie*, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

### **Injury and Causal Link**

10. Information of three petitioner companies, after excluding WS Industries, has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Petitioners have furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, significant price undercutting and price depression and consequent significant adverse impact in terms of production, capacity utilization, domestic sales volumes, inventories, market share, profits, return on capital employed, and cash flow for the domestic industry. There is sufficient evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

### **Period of Investigation**

11. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from 1<sup>st</sup> January, 2011 to 31<sup>st</sup> December, 2011. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. Apr'08-Mar'09, Apr'09-

Mar'10, Apr'10-Mar'11 and the proposed period of investigation has been considered. For threat of material injury, the data beyond the POI would also be examined.

### **Submission of information**

12. The known exporters in the subject country and its Government through its Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce,  
Room No.240, Udyog Bhawan,  
New Delhi -110107.**

### **Time limit**

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

### **Submission of Information on Non-Confidential basis**

14. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

15. Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

### **Inspection of Public File**

16. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing the non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

17. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority